

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Pal Singh Tomar.

Need to establish a separate bench of the Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आए हुए मेरा यह करीब तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष में मैंने एक विषय उठाया था, जिसे मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 22 जिले हाई कोर्ट की बेंच को लेकर आंदोलनरत हैं। दो वर्ष पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधि मंत्री जी से मिला था। उन्होंने वहां सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए विचार करने को कहा था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। हमारे यहां 750 किलोमीटर दूर सहारनपुर हाई कोर्ट से पड़ता है, मेरठ 620 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों की राजधानियों के हाई कोर्ट्स उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से नजदीक हैं। इस कोरोना के काल में बहुत से गरीब लोग न्याय से वंचित रह गए हैं इसलिए मुझे दोबारा यह विषय उठाने की आवश्यकता पड़ी।

उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 23 करोड़ है। कई देशों की आबादी इससे कम है। हमारे राज्य का क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में करीब नौ लाख से ज्यादा केसेज़ पेंडिंग हैं। इनमें से करीब 50 प्रतिशत इन 22 जिलों के हैं जहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जहां हाई कोर्ट की चार-चार बेंचें हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए चार बेंच भी बना दी जाएं, गोरखपुर, आगरा और मेरठ, तब भी कम हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इस विषय पर बात होती है तो कहा जाता है कि इसके लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमंडेशन की आवश्यकता है, लेकिन यह केस अलग है। प्रदेश सरकार दो बार रिकमंड कर चुकी है, जसवंत सिंह आयोग बना, उसकी रिकमंडेशन आई है। जब Reconstitution of the State Act, 1956 बना, तो उसमें यू.पी. और बिहार अलग रखे गए थे। बिहार में रांची में जो बेंच बनी थी, वह केन्द्र द्वारा कानून बनाकर ही बनी थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये 22 जिले मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलनरत हैं, इस बेंच को स्थापित किया जाए।

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

Need to enact Women Reservation Bill and obligatory paternity leave to bridge gender pay gap in the country

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, Article 39 of our Constitution promises equal pay for equal work for both men and women. We also have the Equal Remuneration Act, 1976. Several judgements of the Supreme Court have emphasized the same point but gender-pay gap still remains a big issue in our country.

India has slipped to the 112th spot from its 108th position in 2018 in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index, 2020 amongst 153 countries. We rank 149th in economic participation and opportunity and 117th in wage equality for similar work. The most distressing fact is that the economic gender gap in our country is larger than the political gender gap. Women are paid most unequally in India compared to men when it comes to hourly wages for labour. A Report by the International Labour Organisation says, "On an average, women are paid 34 per cent less than men." Many researches also said that one of the main issues here is the cultural norms where woman is projected as the primary care-giver, the person who raises the family. Even if she has attained the position of a doctor, a lawyer or Head of State, that stereotype remains. Many of the factors causing this pay gap have, of course, declined over the years, but this stereotype remains. There is a term that is popularly called 'motherhood penalty'. Many studies have said that this motherhood penalty results in loss of about 20 per cent in the income of woman. I would like to point out two countries. One is Rwanda. This is one country where 30 per cent of representatives at all levels of Government are women; 61 per cent of the seats in Parliament, the highest in the world, are women; female labour force participation is 88 per cent and the gender pay gap is the lowest, that is, 86 per cent women get almost the same pay as the men get. Similarly, the other country is Iceland. They have done it through legislation. In India, the National Human Rights Commission has made several recommendations. Now, I would like to make these suggestions based on those two recommendations. One, more women should be in positions of decision making. That could be done through Women's Reservation Bill. The second and very important is, changing the expectation that women should be the